मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और एडीबी कंट्री डायरेक्टर मियो ओका की मुलाकात

350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने में एडीबी महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर, 30 अप्रेल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया है कि प्रदेश को वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने में एशियन डवलपमैंट बैंक (एडीबी) महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी, निर्वाह करेगा। उन्होंने शहरी विकास और सड़क निर्माण के अलावा, अन्य क्षेत्रों में भी एडीबी के साथ साझेदारी बढ़ाए जाने पर बल देते हुए कहा कि 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने के लिए एडीबी का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को एशियन डवलपमैंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर मियो ओका से मुलाकात की। उन्होंने एडीबी के 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल के साथ प्रदेश के सड़क तंत्र के उन्नयन, बुनियादी ढांचे के विकास सहित, विभिन्न विषयों एवं संभावित निवेश पर चर्चा की।

■ **सड़क तंत्र, बुनियादी ढांचे के विकास सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई।**

मुख्यमंत्री ने बुधवार को एडीबी के 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल के साथ प्रदेश के सड़क तंत्र के उन्नयन, बुनियादी ढांचे के विकास सहित, विभिन्न विषयों एवं संभावित निवेश पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि विकास की हमारी साझा प्राथमिकताओं में एडीबी का हमेशा से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि एडीबी और राजस्थान द्वारा साथ मिलकर कार्य करने से रणनीतिक साझेदारी के साथ-साथ रोजगार के अवसरों को गति मिलेगी।

शर्मा ने कहा कि वर्तमान में राज्य के शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए आरयूआईडीपी परियोजना एवं सड़क क्षेत्र के उन्नयन के लिए राजस्थान हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के माध्यम से एडीबी सहयोग कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पेयजल एवं सिंचाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एडीबी से इस दिशा में सहयोग की पेशकश की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) के अंतर्गत, शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के राज्य सरकार के संकल्प में भी एडीबी साझेदार रहेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए राजमार्ग विकास परियोजनाओं में भी एडीबी की भागीदारी रहेगी।

बैठक में कंट्री डायरेक्टर ओका ने देश में ग्रीन बजट लाने की राजस्थान की अभिनव पहल की प्रशंसा करते हुए, जैव विविधता, ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन-ऑडिट, क्लीन टेक्नोलोजी के क्षेत्रों में एडीबी के सहयोग का प्रस्ताव किया। साथ ही, रोजगार, कौशल विकास, सूक्ष्म-सिंचाई, वानिकी व पर्यावरण जैसे नवीन क्षेत्रों के वित्त-पोषण हेतु एडीबी अधिकारियों ने रूचि दिखाई।

इस दौरान उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, नगरीय विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा एवं वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

भारतीय आकाश में नहीं उड़ेंगे पाक विमान

नई दिल्ली, 30 अप्रैल। भारत ने बुधवार देर रात पाकिस्तान के लिए अपना एयरबेस बंद कर दिया। यानी पाकिस्तान की किसी भी तरह की फ्लाइट 23 मई तक भारतीय एयरस्पेस में नहीं उड़ सकेंगी।

भारत ने पाकिस्तान के लिए "नोटिस टु एयरमैन" जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई फ्लाइट इंडियन जोन में आती है, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल को भारत के लिए अपना एयरस्पेस बंद करने का फैसला लिया था।

यह फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और सेना प्रमुख उपेन्द्र द्विवेदी की हाई लेवल मीटिंग के बाद आया। यह मीटिंग एक घंटे चली।

■ **भारत ने पाकिस्तान के विमानों के लिए 23 मई तक एयरस्पेस बंद करने की घोषणा की।**

हालांकि यह नहीं बताया गया कि एयरस्पेस बंद करने का फैसला इसी बैठक में लिया गया। एयरस्पेस बंद करने से पाकिस्तान की इकॉनोमी पर बड़ा असर पड़ेगा। पाकिस्तान को थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका आदि देशों में अपने विमान भेजने के लिए काफी लंबा रूट लेना होगा। इससे वहां की हवाई यात्रा महंगी होगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा के लिए प्र.मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।

हनुमानगढ़ी के गद्दीनशीन महंत ने 288 साल की परम्परा तोड़ी, रामलला के दर्शन किए

हनुमानगढ़ी की परम्परा है कि गद्दीनशीन महंत हनुमानगढ़ी की सीमा (52 बीघा) से कभी बाहर नहीं जाते हैं

अयोध्या, 30 अप्रैल। सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी मंदिर के गद्दीनशीन महंत 288 साल की परंपरा को तोड़कर अक्षय तृतीया के दिन शाही जुलूस के साथ रामलला के दर्शन के लिए निकले। सुबह 7.30 बजे घोड़ा, हाथी और बैंड बाजे के साथ हनुमानगढ़ी के निशान के साथ गद्दीनशीन सरयू घाट पहुंचे। स्नान के उपरान्त, सरयू नदी में दुग्धाभिषेक किया और 11 मीटर की चुनरी चढ़ाई। इसके बाद वहां से शोभा यात्रा राम पथ के रास्ते राम मंदिर परिसर पहुंची, जहां राम मंदिर में दर्शन-पूजन के साथ गद्दीनशीन प्रेमदास ने रामलला को छप्पन भोग का प्रसाद भी अर्पित किया।

■ **अक्षय तृतीया पर गद्दीनशीन महंत प्रेमदास शोभायात्रा के साथ रामलला के मंदिर आए और रामलला को छप्पन भोग अर्पित किया।**

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हनुमानगढ़ी के गद्दीनशीन का पद बहुत महत्वपूर्ण और प्रमुख होता है। गद्दीनशीन अपने जीवन काल में कभी भी हनुमानगढ़ी के सीमा 52 बीघा के बाहर नहीं निकल सकता। हनुमान जी के प्रतिनिधि के तौर पर गद्दीनशीन को माना जाता है। हनुमानगढ़ी के गद्दीनशीन प्रेमदास जी की इच्छा के अनुसार पंचायत के निर्णय के बाद 288 सालों के इतिहास में पहला मौका था, जब हनुमानगढ़ी का कोई गद्दीनशीन रामलला का दर्शन करने के लिए गए। इस दौरान अयोध्या के साधु संतों में खासा उत्साह दिखा। 51 जगह पर पुष्प वर्षा के साथ शाही जुलूस का स्वागत किया गया। प्रेमदास ने रामलला के दर्शन की इच्छा जताई थी। कहा था- मेरे सपने में हनुमान जी आए थे। उन्होंने रामलला के दर्शन करने का आदेश दिया था। इसके बाद उन्होंने अखाड़े के सभी सदस्यों की 21 अप्रैल को बैठक बुलाई।

इस बैठक में परंपरा बदलने के फैसले पर मुहर लगी। तय हुआ, प्रेमदास रामलला के दर्शन करने जाएंगे। संत प्रेमदास 2016 में हनुमानगढ़ी के 22वें गद्दीनशीन महंत बने थे।

हाई कोर्ट ने तलाकशुदा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याचिकाकर्ता की मां की भी मौत हो गई। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता का अपने पति से तलाक हो गया था और कोर्ट से नवंबर,1979 में तलाक की डिक्री जारी होने के बाद से वह अपने माता-पिता के साथ ही रहती आ रही थी। मां के निधन के बाद याचिकाकर्ता ने साल 2019 में फैमिली पेंशन के लिए विभाग में प्रार्थना पत्र दिया, जिसे विभाग के अफसर एक दूसरे को भेजते रहे, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस पर याचिकाकर्ता ने तलाकशुदा पुत्री वर्ग में फैमिली पेंशन लेने के लिए पुन: प्रार्थना पत्र दिया। याचिका में कहा गया कि बीते करीब चार साल से विभाग न तो उसके प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर रहा है और न उसे फैमिली पेंशन जारी कर रहा है। याचिका पर सुनवाई के दौरान, शिक्षा विभाग की ओर से मामले में अपना जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा गया।

इस पर अदालत ने याचिकाकर्ता को तलाकशुदा पुत्री वर्ग में फैमिली पेंशन जारी करने के आदेश दिए हैं।

दुष्कर्म पीड़िता ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नहीं रखना चाहती है। ऐसे में उसे 20 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने की मंजूरी दी जाए। सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में एसएमएस अस्पताल की ओर से पीड़िता का परीक्षण कर मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। जिसमें माना गया कि पीड़िता के 20 सप्ताह का गर्भ है। वहीं, यदि उसका गर्भपात किया गया तो उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि पीड़िता को खून की कमी है।

गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुले

इसी के साथ चार धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है

उत्तरकाशी, 30 अप्रैल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद अंतर्गत स्थित मां श्री गंगोत्री और श्री यमुनोत्री धाम के कपाट बुधवार को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजा-अर्चना के मध्य, श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। इसके साथ ही, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 2025 का भी शुभारंभ हो गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों धामों में कपाटोद्घाटन समारोह में संकल्प लेकर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम से पहली पूजा की और चारधाम यात्रा के सफल आयोजन तथा देश-प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की मंगल कामना की है। धामी यमुनोत्री धाम के कपाटोद्घाटन में पहुंचने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। इस अवसर पर गंगोत्री एवं यमुनोत्री मंदिर के ऊपर हैलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। धार्मिक परंपराओं के अनुसार, बुधवार सुबह मां गंगा की उत्सव डोली भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर से चलकर गंगोत्री धाम पहुंची, जहां विशेष पूजा-अभिषेक के साथ, पूर्वाह्न 10 बजकर 30 मिनट पर गंगोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गये। मां यमुना की डोली शनिदेव महाराज की अगुवाई में शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली से चलकर यमुनोत्री धाम पहुंची, जहां धार्मिक विधि- विधान के साथ पूर्वाह्न 11 बजकर 55 मिनट पर यमुनोत्री धाम के कपाट दर्शनार्थ खोले गए। कपाट खुलने के अवसर पर देश, विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं ने अखंड ज्योति के दर्शन किये तथा गंगा और यमुना में स्नान कर पुण्य अर्जित किया। दोनों धामों के कपाटोद्घाटन समारोह में प्रतिभाग करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने माँ गंगा एवं यमुना के मंदिरों में शीश नवाया और विशेष पूजा-अर्चना की। उन्होंने दोनों धामों में पहुँची लोक देवताओं की डोलियों से भी आशीष प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। उत्तराखंड के चारधाम देश-विदेश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था के प्रमुख केन्द्र हैं और इन धामों की यात्रा का सौभाग्य प्राप्त करने की आकांक्षा हर श्रद्धालु के मन में रहती है।

■ **उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर विशेष पूजा की, खासतौर पर पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम से हुई।**

अल्ट्रा साउण्ड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आवेदन मांगे थे। इसमें प्रावधान किया गया कि पहले राउंड में प्रदेश की मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले चिकित्सकों और सेवारत डॉक्टरों को शामिल किया जाएगा। वहीं, यदि बाद में सीटें खाली रही तो दूसरे और बाद के राउंड में प्रदेश के बाहर से एमबीबीएस करने वालों को मौका मिलेगा। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि नेशनल मेडिकल कमीशन देश में कहीं से भी एमबीबीएस करने वाले चिकित्सकों को योग्यता के आधार पर एक समान मानता है। ऐसे में कोर्स में प्रवेश के लिए प्रार्थी के साथ जगह के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। पीसीपीएनडीटी नियम, 2014 के तहत, नीट पीजी के अंकों के आधार पर इस कोर्स में प्रवेश देने का प्रावधान है। यह शर्त संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। प्रार्थी ने गुजरात से एमबीबीएस किया है और वह नेशनल मेडिकल कमीशन से मान्य है। इसलिए उसे कोर्स की काउंसलिंग में शामिल करें। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से मामले में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया। इस पर अदालत ने याचिकाकर्ता को प्रथम राउंड की काउंसलिंग में शामिल करने को कहा है।

सेना की मदद के लिए रेल्वे ने किए महत्वपूर्ण बदलाव

रेल्वे ने कई गाड़ियों के रुट बदल दिए, ताकि, आपात स्थिति के लिए ट्रैक को खाली रखा जाए

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सीमा पर उत्पन्न परिस्थितियों में सशस्त्र बलों को रसद आपूर्ति के लिए लाइनें खाली रखने एवं पथ उपलब्ध कराने को लेकर रेलवे में तैयारियां जोरों पर हैं।

रेल भवन में मंगलवार शाम हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में रेलवे एवं सेना के उच्चाधिकारी शामिल हुए। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सीमापार सैन्य कार्रवाई की तैयारियों के बीच सेना ने रसद आपूर्ति, सैन्य साजो सामान एवं सैनिकों के द्रुत गति से परिवहन के लिए रेलवे से लाइनों को खाली रखने एवं मार्ग उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे ने प्रमुख सैन्य छावनियों एवं रक्षा उत्पादन इकाइयों से सामरिक बिन्दुओं तक के मार्ग से केवल आवश्यक गाड़ियों को चलाने, अतिरिक्त या कम महत्वपूर्ण गाड़ियों का रास्ता बदलने का निर्णय लिया है। इसी तरह से अनेक ज़ोनों में कम लोकप्रिय गाड़ियों को रद्द किया गया है और उनके रैक को आपात स्थिति के लिए सुरक्षित किया जा रहा है।

■ **सेना ने पहलगाम हमले के बाद सीमा पर उत्पन्न हालात को देखते हुए सैनिकों की आवाजाही व रसद आपूर्ति के लिए रेल्वे ट्रैक खाली रखने का आग्रह किया था रेल्वे से।**

बताया गया है कि रेलवे के दोनों समर्पित मालवहन कॉरीडोर भी सैन्य परिवहन के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कंटेनर परिवहन के काम आने वाले मालगाड़ी रैक भी टैंकों एवं बख्तरबंद वाहनों, तोपों एवं गोला बारूद के परिवहन के लिए उपयुक्त रैक एवं कंटेनरों को भी सेना के अधिकारियों के साथ मिल कर जुटाया जा रहा है।

यह भी पता चला है कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर की सीमा के अलावा बंगलादेश से लगती पश्चिम बंगाल, असम सहित पूर्वोत्तर की लाइनों को भी सैन्य परिवहन के हिसाब से तैयार रखने के निर्देश दिये गये हैं।

पाकिस्तान ने पांचवे दिन भी सीमा पर फायरिंग की

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल। पाकिस्तानी सेना ने लगातार पांचवें दिन मंगलवार रात को भी जम्मू- कश्मीर के नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टरों में नियंत्रण रेखा पर बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की।

सेना के प्रवक्ता ने बुधवार सुबह बताया कि इसके अलावा पाकिस्तानी सेना की चौकियों से बारामुला और कुपवाड़ा जिलों में नियंत्रण रेखा के पार से और परगवाल सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार से भी बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई।भारतीय सेना के जवानों ने तेजी से और आनुपातिक रूप से इसका उचित जवाब दिया।

■ **सेना के प्रवक्ता ने बताया कि कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग का भरतीय सेना ने करारा जवाब दिया।**

मंगलवार को संघ प्रमुख...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सबक मिले, जिसे वे कभी भूल नहीं सकें।

जातिगत जनगणना की घोषणा पर, राहुल ने कहा कि वे बहुत प्रसन्न हैं कि सरकार ने इसकी घोषणा कर दी। लेकिन अपनी इस जीत पर केवल खुश होने के बजाय, उन्होंने इस जनगणना के लिये आगामी रुपरेखा भी प्रस्तुत कर दी।

उन्होंने कहा कि तेलंगाना के जातिगत सर्वे के अनुरुप, सर्वे की रुपरेखा तैयार करने में कांग्रेस सरकार की मदद करने के लिये तैयार है, जिससे लोगों से सही एवं सटीक प्रश्न पूछे जायें और उनके सही एवं सटीक उत्तर मिलें, जिससे सही डेटा सामने आये, जिससे लोगों की मदद की जा सके तथा सर्वे उनके लाभ के लिये काम कर सके।

उन्होंने कहा कि सरकार को 50 प्रतिशत आरक्षण के बैरियर को भी तोड़ ही देना चाहिये। यह सीमा ओबीसी, दलितों, आदिवासियों तथा अन्य की उन्नति में बाधा बन गई है।

राहुल ने यह भी कहा है कि सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि अनुच्छेद 15 (5) लागू हो गया है या नहीं। यह कानून निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान करता है। उन्होंने कहा कि संविधान में यह आधारभूत अधिकार दिया हुआ है, लेकिन यह लागू नहीं हुआ है।

राहुल ने अपना अगला एजेंडा आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने सरकार को चेताया है कि उसे जातिगत जनगणना की समय सीमा की घोषणा कर देनी चाहिये। उन्होंने कहा कि यह सर्वे औपचारिक मात्र बन कर न रह जाये, बल्कि पूरी ईमानदारी से तथा सुविचारित तरीके से हो। उन्होंने कहा कि यह सर्वे तेलंगाना मॉडल के अनुरुप हो, बिहार मॉडल के अनुरुप नहीं।

राहुल गांधी ने, जातिगत घोषणा के बाद का, अपना अगला एजेंडा प्रस्तुत कर दिया है तथा यह दिलचस्पी पैदा करने वाला है।

राहुल ने कहा कि उनकी इस प्रश्न में कोई रुचि नहीं है कि यह निर्णय एकाएक क्यों और कैसे लिया गया, बल्कि वे इस बात से प्रसन्न है कि यह निर्णय ले लिया गया है।

'अगली जनगणना "जातिगत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मजबूत होगा, देश प्रगति करेगा।

कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया ने पूर्व चुनाव में जातिगत जनगणना को प्रमुख मुद्दा बनाया था। राहुल गांधी ने आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने का वादा किया था।

जनगणना की कवायद अप्रैल 2020 में शुरु होनी थी, पर कोविड के कारण शुरु नहीं हो पाई थी।

वैष्णव ने कहा, वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जातिगत जनगणना पर मंत्रिमंडल में विचार किया जाएगा। इसके लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन भी हुआ था क्योंकि कई दलों ने जातिगत जनगणना करवाने की मांग की थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने सिर्फ एक सर्वेक्षण कराया, जातिगत जनगणना नहीं करवाई। उक्त सर्वे को एसईसीसी के नाम से जाना जाता है।

मंत्री ने कहा, स्पष्ट है कि कांग्रेस और उसका इंडिया गठबंधन, जातिगत जनगणना के मुद्दे को राजनैतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।

वैष्णव ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना एक केन्द्रीय विषय है (संघ सूची में प्रविष्टि 69 के तहत) और केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

कुछ राज्यों ने जातियों की गणना के लिए सर्वेक्षण किए हैं, कुछ ने यह कार्य अच्छे ढंग से किया जबकि कुछ ने केवल राजनीतिक मकसद से इसे अपारदर्शी तरीके से किया जिससे समाज में संदेह पैदा हुआ।

उन्होंने कहा, "यह दिखाता है कि हमारी सरकार समाज और देश के हितों के लिए प्रतिबद्ध है, जैसे पहले हमने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया था बिना किसी अन्य वर्ग पर बोझ डाले।"

कांग्रेस और लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल ने केन्द्र के इस कदम का श्रेय खुद को दिया है। बिहार में चुनाव नज़दीक हैं और वहाँ की महागठबंधन सरकार ने सबसे पहले जाति सर्वे किया था, उनका मत है कि केन्द्र का यह निर्णय उनके दबाव में लिया गया है।

राजद प्रमुख लालू यादव ने कहा, "जो हम समाजवादियों ने 30 साल पहले सोचा- आरक्षण, जाति जनगणना, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता- बाकी लोग उसे दशकों बाद अपनाते हैं।"

उन्होंने कहा, "जाति जनगणना की मांग करने पर हमें "जातिवादी" कहने वालों को करारा जवाब मिला है। अभी बहुत कुछ बाकी है।"

अमेरिका की जीडीपी 0.3 प्रतिशत...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आएगा और जब ऐसा होगा तो यह बहुत ऊँचाई तक जाएगा।

हालांकि, शेयर बाजार राष्ट्रपति की बातों से सहमत नहीं लग रहा। प्रमुख बाजार सूचकांकों में तेज गिरावट आई है। डाओ जोंस इण्डैक्स, जो व्यापक आर्थिक क्षेत्रों का मापदंड है, 400 अंक (या एक प्रतिशत) गिर गया।

अन्य दो प्रमुख सूचकांक, एसएंडपी 500 में 1.5 प्रतिशत की गिरावट आई, और तकनीकी कंपनियों वाले नैसडैक में 2.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट शेयर बाजार की समग्र गिरावट को दर्शाती है। पिछली बार इतनी व्यापक गिरावट 2007 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान देखी गई थी।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था कई मायनों में भारत जैसी है। यहां भी घरेलू उपभोग व्यय (डॉमैस्टिक कंज़म्पशन एक्स्पैन्डिचर) अर्थव्यवस्था की गति तय करता है। जी.डी.पी. आंकड़े उपभोक्ता के विश्वास की स्थिति को दर्शाते हैं। इस वर्ष की पहली तिमाही में उपभोक्ता खर्च में केवल 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसके पहले के तीन महीनों में यह 4 प्रतिशत थी। यह दर्शाता है कि उपभोक्ता विश्वास किस हद तक आहत हुआ है और डिस्पोज़ेबल इन्कम (खर्च करने योग्य आय) में किस हद तक मंदी देखी जा रही है।

दूसरी ओर, करन्ट अकाउन्ट डैफिसिट (चालू बजट घाटा) भी बढ़ रहा है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, मार्च में अमेरिकी माल में यू.एस. ट्रेड डैफिसिट 9.6 प्रतिशत बढ़कर 162 बिलियन डॉलर हो गया, जो फरवरी में 147.8 बिलियन डॉलर था।

यानी अमेरिका अभी भी अपने निर्यात से ज्यादा आयात कर रहा है- यह उस स्थिति के बिल्कुल विपरीत है जो ट्रंप अपने टैरिफ वॉर से हासिल करना चाहते थे। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कंपनियों ने ट्रंप टैरिफ की आशंका में कई महीनों का माल पहले ही आयात कर लिया है।

एलन मस्क के मार्गदर्शन में ट्रंप प्रशासन की सरकारी खर्च में कटौती की नीति के कारण, सरकारी खर्च और सरकारी नौकरियों मे गिरावट आई है। इसका सीधा असर अमेरिकी उपभोक्ताओं के इस वर्ग की खपत पर पड़ रहा है।

इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, डॉनल्ड ट्रंप आत्मविश्वास से भरे नज़र आ रहे हैं और सभी दोष पूर्ववर्ती प्रशासन और उनकी नीतियों पर डाल रहे हैं। फिर भी, ट्रंप ने अमेरिकी जी.डी.पी. में गिरावट पर चर्चा और मूल्यांकन के लिए कैबिनेट बैठक बुलाई है। जाहिर है कि शुरुआती रिपोर्टों से उभरते रुझानों को लेकर प्रशासन में चिंता व्याप्त है।

पहलगाम की घटना ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के क्रियान्वयन के कारण पर्यटन अपनी योजनाएं बदल रहे हैं।

दूसरी ओर, उत्तराखंड जहाँ मसूरी, नैनीताल और ऋषिकेश जैसे प्रमुख हिल स्टेशन है, में बुकिंग तेज़ी से बढ़ी है। अप्रैल 2024 में जहाँ ऑक्युपेंसी 70 प्रतिशत थी, वहीं अप्रैल 2025 में यह बढ़कर 85 प्रतिशत हो गई, यानी 15 प्रतिशत की वृद्धि। खासतौर पर परिवारों और वरिष्ठ नागरिकों ने अब उत्तराखंड को अपनी यात्रा के लिए के रूप में चुना है, जो उन्हें अधिक सुरक्षित और शांतिपूर्ण लग रहा है।

हिमाचल प्रदेश में भी मध्यम स्तर की वृद्धि हुई है, अप्रैल 2024 में 75 प्रतिशत ऑक्युपेंसी थी, जो इस वर्ष 80 प्रतिशत हो गई है, यानी 5 प्रतिशत की वृद्धि। हालांकि, उत्तराखंड जितनी तेजी नहीं दिखी, लेकिन हिमाचल को भी कश्मीर के विकल्प के रूप में चुना जा रहा है।

2024 में दिल्ली, पंजाब और गुजरात के पर्यटकों की कश्मीर पहली पसंद था, लेकिन इस वर्ष रुझान बदला है, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत से उत्तराखंड और हिमाचल की ओर बढ़ता रुझान देखने को मिल रहा है।

पर्यटन उद्योग के जानकारों का कहना है कि आने वाले 10-15 दिन यह तय करने में महत्वपूर्ण होंगे कि यह केवल अस्थायी प्रतिक्रिया है या एक बड़ा बदलाव है। इस बीच, हिमाचल और उत्तराखंड के राज्य पर्यटन विभागों ने इस प्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए डिजिटल प्रचार-प्रसार बढ़ा दिया है। "शांतिपूर्ण समर गेटवेज़" और "सुरक्षित पारिवारिक हिल हॉलिडे" जैसे नारों के साथ प्रचार कर रहे हैं।

सिलचर से शिलांग के बीच 166 किलोमीटर लंबा गलियारा बनेगा

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक में यह फैसला किया गया

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल। केन्द्र सरकार ने असम के सिलचर से मेघालय के शिलांग के बीच 22 हजार 864 करोड़ रूपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या छह के 166.80 किलोमीटर लंबे गलियारे के हिस्से के विकास , रख रखाव और प्रबंधन के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी।

इसे हाइब्रिड एन्युटी मोड पर एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जायेगा।

इस परियोजना के तहत मेघालय में 144.80 किलोमीटर और असम में 22 किलोमीटर हिस्सा आयेगा। प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर गुवाहाटी से सिलचर तक जाने वाले यातायात के लिए सेवा स्तर में सुधार करेगा। इस कॉरिडोर के विकास से मुख्य भूमि और गुवाहाटी से त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और असम के बराक घाटी क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और यात्रा की दूरी और यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। यह गलियारा असम और मेघालय के बीच संपर्क में सुधार करेगा और मेघालय में उद्योगों के विकास सहित आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, क्योंकि यह मेघालय के सीमेंट और कोयला उत्पादन क्षेत्रों से होकर गुजरता है। यह गलियारा गुवाहाटी हवाई अड्डे, शिलांग हवाई अड्डे, सिलचर हवाई अड्डे (मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग-06 के माध्यम से) से आने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को सेवा प्रदान करेगा, जो गुवाहाटी को सिलचर से जोड़ता है।

■ **इस कॉरिडोर के विकास से मेन लैण्ड और गुवाहाटी से त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर और असम के घाटी क्षेत्र से कनैक्टिविटी बढ़ेगी।**

यह पूर्वोत्तर में पर्यटकों के आकर्षण के सुंदर स्थानों को जोड़ेगा और पर्यटन को बढ़ावा देगा। यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना गुवाहाटी, शिलांग और सिलचर के बीच अंतर-शहर संपर्क में सुधार करेगी, जो री भोई, पूर्वी खासी पहाड़ियों, पश्चिम जैंतिया पहाड़ियों, मेघालय में पूर्वी जैंतिया पहाड़ियों और असम में कछार जिले से होकर गुजरती है।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:**-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908